



भारत और नई विश्व व्यवस्था

यह एडिटरियल 05/09/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "At G20, the end of old multilateralism – and the beginning of a new order" लेख पर आधारित है। इसमें पारंपरिक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के पतन और एक नई विश्व व्यवस्था के उद्भव के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ इस रूपांतरण में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है।

परलिम्स के लिये:

[वैश्वीकरण](#), [जलवायु परिवर्तन](#), [G20](#), [G7](#), [संयुक्त राष्ट्र \(United Nations\)](#), [आईएमएफ](#), [विश्व बैंक](#), [ब्रिक्स](#), [अफ्रीकी संघ](#), [दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन \(आसियान\)](#), [यूरोपीय संघ](#), [क्वाड](#), [AUKUS](#), [ग्लोबल साउथ](#)

मेन्स के लिये:

नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, मौजूदा पारंपरिक बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के पतन के पीछे के कारण, नई विश्व व्यवस्था के रूपांतरण में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका

यह स्पष्ट है कि **शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता (multilateralism)**, जिसमें विभिन्न देशों के बीच सहयोग शामिल है, वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अपने नमिन स्तर पर पहुँच गया है। हाल ही में जकार्ता में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) और दल्लि में आयोजित **G20** शिखर सम्मेलन से यह परिदृश्य स्पष्ट हो गया है, जो वैश्विक सहयोग की पछिली प्रणाली में वदियमान गंभीर और संभवतः स्थायी समस्याओं को रेखांकित करते हैं।

शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि को संदर्भित करती है, जब विश्व भर के कई देश **व्यापार**, **सुरक्षा**, **मानवाधिकार** और **पर्यावरण संरक्षण** जैसे मुद्दों पर विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं समन्वय में संलग्न हुए थे। यह दो **महाशक्तियों- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ** तथा उनके अपने-अपने सहयोगियों के बीच बड़े संघर्षों की अनुपस्थिति से सुगम हुआ। शीत युद्धोत्तर बहुपक्षीयता लोकतंत्र, वधिक शासन और मुक्त बाज़ार जैसे उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी तथा इसे **संयुक्त राष्ट्र (United Nations)**, **यूरोपीय संघ (EU)**, **आसियान (ASEAN)** और **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** जैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था।

नई विश्व व्यवस्था (New World Order) क्या है?

नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था (new multilateral world order) पद 21वीं सदी में विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच सहयोग एवं संवाद के नए रूपों के उद्भव को संदर्भित करता है। यह **वैश्वीकरण**, **जलवायु परिवर्तन**, **महामारी**, **आतंकवाद** और **अन्य मुद्दों से उत्पन्न चुनौतियों** एवं अवसरों पर एक प्रतिक्रिया है जिसके लिये सामूहिक कार्रवाई और साझा समाधान की आवश्यकता होती है।

नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की कुछ प्रमुख बातें:

- विकासशील विश्व और 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) से वृहत अभिव्यक्तियों और दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिये **संयुक्त राष्ट्र**, **IMF** और **विश्व बैंक** जैसे मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों का वसितार एवं विधिीकरण।
- ब्रिक्स (BRICS)**, **अफ्रीकी संघ (AU)**, **आसियान (ASEAN)** और **यूरोपीय संघ (EU)** जैसे नए क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण और सुदृढीकरण, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण, विकास, सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।
- अनौपचारिक नेटवर्कों और पहलों का उद्भव—जैसे अलायंस फॉर **मल्टीलैटरलिज़्म (Alliance for Multilateralism)**, **G20** और **क्वाड (QUAD)**, जो ऐसे विशिष्ट मुद्दों या चुनौतियों के समाधान पर लक्षित हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे असर रखता हैं और समन्वित कार्रवाई की मांग करते हैं।
- विश्व की बहुध्रुवीय वास्तविकता को चिह्नित करना, **जहाँ कोई भी एक देश या गुट वैश्विक एजेंडे पर हावी नहीं हो सकता या उसे निर्देशित नहीं कर सकता** और जहाँ विभिन्न अभिक्रियाओं को सहमत और पारस्परिक लाभ की खोज में संवाद एवं समझौता वार्ता में शामिल होना पड़ता है।

मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्रमुख कारण:

- चीन का उदय और उसका वसितारवाद:** मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन के पीछे के प्रथमिक कारणों में से एक है **वैश्विक आर्थिक एवं सैन्य शक्ति**

के रूप में चीन का उदय। एशिया में और वैश्विक स्तर पर चीन की वसितारवादी नीतियाँ मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था को चुनौती देती हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बदलने के इसके एकतरफा प्रयासों और इसके मुख्य क्षेत्रीय वसितारवाद ने तनाव उत्पन्न किये हैं तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक संस्थाओं को अस्थिर कर दिया है।

- चीन की ओर से आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरे: चीन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और सुरक्षा संबंधी खतरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत जैसे देशों को चीन के साथ अपने संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिये विवश किया है। इस क्रम में चीन के ऊपर व्यापक आर्थिक अंतर नरिभरता को जोखिम-मुक्त करने के प्रयास शुरू हो गए हैं, जिसका मौजूदा बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों पर प्रभाव पड़ रहा है।
- रूस की कार्रवाई: वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के आक्रमण एवं अधिग्रहण ने शीत युद्धोत्तर सुरक्षा व्यवस्था के लिये एक महत्वपूर्ण चुनौती को चिह्नित किया, विशेष रूप से यूरोप में। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दार और संघर्ष पैदा कर बहुपक्षीयता को बाधित कर दिया।
- बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर मौजूद वरिधाभास: बहुपक्षीय प्रणाली को स्वयं आंतरिक वरिधाभासों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सदस्य देशों के बीच इन आंतरिक असहमतियों और परस्पर-वरिधी हतियों ने बहुपक्षीय संगठनों की प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया है तथा सर्वसम्मति निर्माण में बाधा उत्पन्न की है।
- वैकल्पिक सुरक्षा मंचों का उदय: चीन के वसितारवाद की प्रतिक्रिया में क्वाड (QUADS), AUKUS और ट्राईलैटरल कॉम्पैक्ट्स (trilateral compacts) जैसे वैकल्पिक सुरक्षा मंच सामने आए हैं। ये मंच पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थानों से परे एक बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे आसियान जैसे मौजूदा क्षेत्रीय संगठनों की नरिंतर प्रासंगिकता एवं केंद्रीयता पर सवाल खड़े होते हैं।
- प्रमुख खलिाड़ियों के बदलते परिप्रेक्ष्य: भारत जैसे प्रमुख खलिाड़ियों के बदलते दृष्टिकोण ने भी मौजूदा बहुपक्षीयता के पतन में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में भारत के उभरते दृष्टिकोण—जो चीन के प्रभुत्व वाले 'एकध्रुवीय एशिया' के बारे में चिंताओं से हटकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों के साथ अधिक सक्रिय संलग्नता की ओर बढ़ा है—ने हृदि-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीयता की गतिशीलता को बदल दिया है।
- वैश्विक वित्तीय संकट और G7 का वसितार: वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने G7 (Group of Seven) का वसितार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया ताकि इसमें मध्य शक्तियों को शामिल करते हुए वैश्विक आर्थिक स्थिरता को पुनर्बहाल किया जा सके। हालाँकि यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने की दृशा में एक सकारात्मक कदम था, इसने मौजूदा बहुपक्षीय ढाँचे की सीमाओं को भी उजागर किया।

भारत नई विश्व व्यवस्था को किस प्रकार आकार दे सकता है?

- भारत वधि के शासन, संप्रभुता के लिये सम्मान और वविादों के शांतपूरण समाधान पर आधारित मुक्त एवं खुले हृदि-प्रशांत क्षेत्र के प्रसार के लिये क्वाड और आसियान के साथ-साथ वभिन्न अन्य क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय मंचों में अग्रणी भूमिका नभिसकता है।
 - भारत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये समान वधिारधारा वाले देशों के साथ अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ा सकता है।
- भारत अपने व्यापार एवं नविश साझेदारों में (विशेष रूप से 'वैश्विक दक्षिण' के देशों के साथ) वविधिता लाकर और वनिरिमाण, सेवाओं एवं नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमताओं का विकास कर पुनःवैश्वीकरण की प्रक्रिया (re-globalisation process) में योगदान दे सकता है।
 - भारत एक अधिक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत वैश्विक शासन प्रणाली का भी वकालत कर सकता है जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविकताओं एवं आकांक्षाओं को प्रतबिबिति करे।
- भारत G20 शखिर सम्मेलन की मेजबानी का उपयोग एक वैश्विक नेता के रूप में अपने वजिन और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन सतत विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति का निर्माण करने के एक अवसर के रूप में कर सकता है।
- भारत साझा हतियों एवं चुनौतियों को उजागर करके और समावेशी एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तावित करके वकिसति और वकिसशील देशों के बीच की खाई को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका नभिसकता है।

अभ्यास प्रश्न: विश्व इस समय एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय देख रहा है। पुरानी विश्व व्यवस्था के पतन के पीछे के कारणों की चर्चा कीजिये और बताइये कि भारत इस संक्रमण में किस प्रकार योगदान दे सकता है।

<https://youtu.be/3TenpuKqf74>

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रलिमिस:

प्रश्न: नमिनलखिति में से किस एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं?

- (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
- (b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड
- (c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वयितनाम
- (d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-and-the-new-world-order>

